बैंक प्रबन्धनकी विफलता

किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी बैंकमें जब कोई व्यक्ति अपना खाता खोलवाता है तो उसे अपनी पहचानके बारेमें भी जानकारी देनी पड़ती है। इनमें नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, आधार कार्ड, पैन नम्बर, पता, आय, ऋण, पारिवारिक आर्थिक विवरणसे सम्बन्धित जानकारी भी शामिल है। इससे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज बैंकमें जमा होते हैं। इसलिए बैंकोंमें ग्राहकोंका केवल धन ही जमा नहीं होता, बल्कि उसका बैंकके प्रति भरोसा भी बड़ी पूंजीके रूपमें जमा होता है। बैंकोंकी जिम्मेदारी केवल ग्राहकके धनकी सुरक्षातक सीमित नहीं है, उसकी डिजिटल पहचान और निजी जीवनसे जुड़ी सूचनाओंकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्रके सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्वीकार किया है कि बड़े पैमानेपर उसके ग्राहकोंकी जानकारी डार्क वेबपर पहुंच गयी है। हैकर ग्रुप 'सिरियसइम' के दावेके बाद १६ अक्तूबरको थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफेंस साइबर एजेंसी और सीईआरटी-इनकी ओरसे अलर्ट मिलनेके बाद एसबीआईने जांच भी शुरू कर दी है। एसबीआईने सेबी और स्टाक एक्सचेंजोंको सूचना देते हुए बताया है कि डार्क वेबपर उपलब्ध लगभग ३.७५ लाख रिकार्डकी प्रारम्भिक जांचमें ३८९७ ग्राहकोंकी व्यक्तिगत जानकारी मिली है। यह हालके वर्षोंमें भारतीय बैंकिंग सेक्टरमें ग्राहकोंकी डेटा चोरीका सबसे बड़ा मामला है। यह ग्राहकोंकी गोपनीयता और वित्तीय सुरक्षाको लेकर गम्भीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे निजी डेटाका दुरुपयोग आसानीसे हो सकता है। यह बैंक प्रबन्धनकी विफलताका प्रमाण है। इस घटनाका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि डेटा चोरी भी आर्थिक अपराधका माध्यम बन सकती है। डेटा चोरीको केवल गोपनीयताका उल्लंघन मानना पर्याप्त नहीं है। इससे वित्तीय ठगीका रास्ता बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि २०२५ के आउटसोर्सिंग निर्देश स्पष्ट करते हैं कि ग्राहकका डेटा किसी सेवा-प्रदाताके पास होनेपर भी उसकी गोपनीयता और अखण्डताकी जिम्मेदारी बैंककी ही रहती है। बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारीसे बच नहीं सकता कि डेटा हमारे सर्वरसे नहीं, हमारे वेंडरसे लीक हुआ है। प्रबन्धनकी जवाबदेही इन सवालोंसे तय होगी कि डेटा बैंकसे बाहर कैसे गया? किस सिस्टम या व्यक्तिके पास अनधिकृत पहुंच थी? क्या जरूरतसे अधिक कर्मचारियों एवं वेण्डरोंको डेटा उपलब्ध था? इसे सीधे तौरपर बैंक प्रबन्धनकी विफलता माना जाना चाहिए क्योंकि ग्राहकोंको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए डेटा लीकपर पूर्ण नियंत्रणकी जरूरत है जिससे कि ग्राहकोंका हित सुरक्षित रह सके।

बुजुर्ग सेवाकी नयी पहल

उत्तर प्रदेश सरकारका बुजुर्गोंकी सेवाके लिए पेशेवर तैयार करनेकी नयी पहल सराहनीय है जिस व्यक्तिने अपने परिवारकी देखभाल करनेमें जीवनका महत्वपूर्ण समय उनकी सेवामें लगा दिया, वहीं वृद्धावस्थामें असहाय और अनाथके तरह अकेलेमें जीवनयापन करे, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है। इस आन्तरिक पीड़ाको भुक्तभोगी ही समझ सकता है। यह तो अच्छा हुआ कि प्रदेशकी योगी आदित्यनाथ सरकारने ऐसे बुजुर्गोंकी पीड़ाको महसूस किया जो मानवीय संवेदनाकी मिसाल है। ऐसे बुजुर्गोंकी सुधि लेते हुए सरकारका 'केयर गिवर्स' (देखभालकर्ता) का विशेष काडर तैयार करनेका निर्णय स्वागतयोग्य है। केयर गिवर्स काडर तैयार करनेकी जिम्मेदारी समाज कल्याण विभागको सौंपना महत्वपूर्ण माना जायगा, क्योंकि यह बुजुर्गोंके समाजके कल्याणके लिए उठाया गया सार्थक कदम है। इससे उन बुजुर्गोंको राहत मिलेगी, जिनके बच्चे रोजगारके सिलसिलेमें बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग घरोंमें रह जाते हैं। इनकी सेवाके लिए कुछ लोग नाते-रिश्तेदारोंकी मदद लेते हैं तो कुछ परिचितोंके सहारे छोड़ देते हैं, जो सरकारके समक्ष बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी देखभालके लिए पेशेवर नहीं मिलते जिससे समस्या दिनोंदिन गहराती जा रही है। केयर गिवर्सके लिए दसवीं और बारहवीं कक्षा पास २० से ४० वर्ष आयुतकके युवक और युवतियोंको कमसे कम ६० घण्टेका प्रशिक्षण दिया जायगा। साथ ही प्रशिक्षणका माड्यूल भी तैयार किया जायगा। प्रशिक्षणमें युवक-युवतियोंको वृद्ध स्वास्थ्य सहायक और वृद्ध शरीर रचनाकी जानकारी दी जायगी। सरकारके इस कदमसे जहां एक ओर बुजुर्गोंकी देखभाल सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारीकी समस्या भी हल करनेमें मदद मिलेगी। पेशेवरोंकी नियुक्तिमें पारदर्शिताके साथ सावधानी बरतनी होगी। साथ ही इनकी निगरानी भी होनी चाहिए ताकि जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए पहल की गयी है उसका सार्थक परिणाम भी धरातलपर दिखे। सरकारकी पहल अन्य राज्योंके लिए भी अनुकरणीय है।

लोक संवाद

नशेके दलदलमें पंजाब

महोदय,-पंजाबमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवालने नशेका मुद्दा उठाकर वादा किया था कि सरकार बननेपर तीन महीनेके भीतर पंजाबको नशामुक्त कर दिया जायगा। पंजाब विधानसभा चुनाव २०२२ के दौरान आम आदमी पार्टीने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन नशामुक्त पंजाबका वादा अधूरा ही है। पंजाब देशके प्रमुख गेहूं उत्पादक और सिंचित कृषि क्षेत्रोंमें शामिल है, लेकिन आज उसी धरतीका युवा नशेके दलदलमें फंसकर अपना भविष्य खो रहा है। नशेकी लतसे परिवारोंकी जमा-पूंजी खत्म हो जाती है, इलाज और नशेकी पूर्तिके लिए कर्ज बढ़ता है और कई परिवार गरीबीके दलदलमें फंस जाते हैं, जिससे पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट झेलता है। दुखद यह है कि यदि कोई नशेके खिलाफ बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। **-महेश कुमार, वाया ईमेल।**

सर्दियोंसे पहले ही प्रदूषणकी चुनौती

सर्दियोंने अभी दस्तक भी नहीं दी है कि देशके अनेक शहरोंकी हवामें प्रदूषणका जहर घुलने लगा है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारतके कई क्षेत्रोंमें वायु गुणवत्ताका तेजीसे बिगड़ना इस बातका संकेत है कि प्रदूषणका संकट अब सर्दियोंकी मौसमी समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधनके सामने गम्भीर चुनौती बन चुका है।

❐ ललित गर्ग

हर साल अक्तूबर-नवंबरमें दमघोंटू धुंध, आंखोंमें जलन, सांस लेनेमें कठिनाई और अस्पतालोंमें बढ़ती मरीजोंकी संख्याके साथ यह संकट सामने आता है। विडंबना यह है कि समस्याके कारणोंकी पहचान होने और उपायोंकी जानकारी उपलब्ध होनेके बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदीको दोहरानेके लिए विवश दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवामें सांस लेना भी अब नागरिकोंके लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जायगा। वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्यकी देन नहीं है। वाहनोंसे निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलोंसे उड़ती धूल, सड़कोंपर जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ जलाना, ताप विद्युत संयंत्रोंसे होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषोंका दहन इसके प्रमुख कारणोंमें शामिल हैं। सर्दियोंमें तापमान गिरने, हवाकी गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियोंके कारण प्रदूषक जमीनके निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषणका प्रभाव अधिक गम्भीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्याको बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले मूल कारण मुख्यत: मानवीय गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन से जुड़े हैं।



प्रदूषण नियंत्रणकी जिम्मेदारी केवल सरकारकी नहीं है। नागरिकोंको निजी वाहनोंका अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जाकी बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमोंके उल्लंघनकी सूचना संबंधित अधिकारियोंतक पहुंचाना एवं हरित क्षेत्र बढ़ानेके प्रयासोंमें भाग लेना भी आवश्यक है। साथ ही वायु गुणवत्ताके आंकड़े पारदर्शी ढंगसे सार्वजनिक किये जायं और नागरिकोंको प्रदूषणके स्तरके अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाय।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस संकटका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्लीके साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपासके अनेक शहर एक-दूसरेसे जुड़े वायु क्षेत्रका हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्लीकी सीमाओंके भीतर उपाय करनेसे समस्याका स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रशासनिक सीमाको नहीं मानती, वह प्रदूषणको भी एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक पहुंचाती है। अत: समाधान भी क्षेत्रीय सहयोग, साझा जवाबदेही और समन्वित कार्ययोजनापर आधारित होना चाहिए। वायु प्रदूषणका सबसे भयावह पक्ष उसका स्वास्थ्यपर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष रूपसे पीएम २.५ जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण फेफड़ोंकी गहराईतक पहुंच सकते हैं और कुछ परिस्थितियोंमें रक्तप्रवाहतक प्रवेश कर सकते हैं। इनके लम्बे समयतक संपर्कमें रहनेसे हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक और समयपूर्व मृत्युका जोखिम बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहलेसे बीमार लोगोंपर इसका प्रभाव विशेष रूपसे गम्भीर हो सकता है।

यह संकट केवल सांसके मरीजोंतक सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले लोगोंकी कार्यक्षमता, एकाग्रता और जीवनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चोंको खुले मैदानमें खेलनेसे रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबहकी सैर छोड़नेको विवश हों और श्रमिकोंको जहरीली हवामें काम करना पड़े तो यह केवल पर्यावरणकी समस्या नहीं, बल्कि जीवनकी गरिमा और नागरिकोंके स्वास्थ्यके अधिकारसे जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ परिस्थितियोंमें व्यक्तिगत बचावमें सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ हवाकी सार्वजनिक व्यवस्थाका विकल्प नहीं बन सकते। प्रदूषण बढ़नेपर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषणकी गम्भीरताके अनुसार निर्माण गतिविधियोंपर प्रतिबंध, वाहनों और उद्योगोंपर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाये जाते हैं। लेकिन इन उपायोंकी सफलता केवल आदेश जारी करनेसे नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निरन्तर निगरानीसे सुनिश्चित होती है। यदि प्रतिबंधोंका उल्लंघन होता रहे, निर्माण स्थलोंपर धूल उड़ती रहे और कचरा खुलेमें जलता रहे तो सरकारी घोषणाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकतीं।

सरकारको प्रदूषणके चरमपर पहुंचनेकी प्रतीक्षा करनेके बजाय सितंबर-अक्तूबरसे ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रदूषणके स्रोतोंकी पहचान, औद्योगिक इकाइयोंका निरीक्षण, सड़कोंकी नियमित सफाई, निर्माण स्थलोंपर धूल नियंत्रण और वाहनोंके उत्सर्जनकी जांच पहलेसे सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहनको मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसोंको बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जाका विस्तार करना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयोंके विरुद्ध निष्पक्ष काररवाई करना दीर्घकालिक रणनीतिका हिस्सा होना चाहिए। कृषि क्षेत्रमें पराली जलानेकी समस्याका समाधान किसानोंपर जुर्माना लगानेभरसे नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषोंके प्रबंधनके लिए सस्ती मशीनें, तकनीकी सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तरपर उपयोगकी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसानोंको समस्याका भागीदार नहीं, समाधानका सहयोगी बनाना होगा। प्रदूषण नियंत्रणकी जिम्मेदारी केवल सरकारकी नहीं है। नागरिकोंको निजी वाहनोंका अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जाकी बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमोंके उल्लंघनकी सूचना संबंधित अधिकारियोंतक पहुंचाना और स्थानीय स्तरपर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढ़ानेके प्रयासोंमें भाग लेना भी आवश्यक है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संघटनोंको जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवाका महत्व केवल प्रदूषणके चरमपर ही याद न आये। साथ ही वायु गुणवत्ताके आंकड़े पारदर्शी ढंगसे सार्वजनिक किये जायं और नागरिकोंको प्रदूषणके स्तरके अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाय।

आज आवश्यकता इस बातकी है कि सरकारें, उद्योग, किसान और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियोंसे पीछे न हटें। चीनके बीजिंग जैसे शहरोंमें प्रदूषण घटानेके अनुभव यह बताते हैं कि निरन्तर नीतिगत प्रयास, स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक नियंत्रण और प्रभावी निगरानीसे उल्लेखनीय सुधार संभव है। भारतको भी अपनी परिस्थितियोंके अनुरूप ऐसे उपायोंको दृढ़तासे लागू करना होगा। हर साल सर्दियोंमें प्रदूषणसे जूझना और फिर मौसम बदलनेपर समस्याको भूल जाना किसी भी संवेदनशील समाजकी नियति नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवनकी बुनियादी आवश्यकता है। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाये गये तो आने वाली पीढ़ियोंको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए प्रदूषणका मुकाबला संकट गहरानेके बाद नहीं, उससे पहले करना होगा। सरकारकी सक्रियता, प्रशासनकी जवाबदेही और जनताकी जागरूकता ही वह त्रिकोण है, जिसके आधारपर हम दमघोंटू हवासे मुक्तिकी दिशामें आगे बढ़ सकते हैं।

लोकतांत्रिक स्वरूपको बिगाड़नेका प्रयास

भारतीय लोकतंत्रमें पार्टियोंका बनना-बिगड़ना कोई नयी बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीशकी बेरोजगारोंसे संबंधित एक टिप्पणीमें 'काकरोच' शब्दसे निकली सोशल मीडियाकी पार्टी काकरोच जनता पार्टी वैसी ही एक पार्टी है।

❐ राधा रमण

अमेरिका रिटर्न महाराष्ट्रके संभाजीनगर निवासी अभिजीत दीपके यह दावा करते हैं कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) चुनावी राजनीतिसे दूर रहनेवाली एक फ्रेशर ग्रुप है। लेकिन सीजेपीके पदाधिकारियोंके ख्वाब बड़े हैं। नीट पेपरलीक मामलेमें केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानके इस्तीफा दे देनेके बाद तो उनकी महत्वाकांक्षा और भी कुलांचे मारने लगी है। मोदी सरकारके कार्यकालमें यह पहला मौका था, जब जनरोषके आगे सरकारको सरेंडर करना पड़ा, वरना पिछले १२ वर्षोंसे तो लोगबाग केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहकी पूर्वमें कही बातको ही सच मान बैठे थे कि यह अलग मिजाजकी सरकार है, यहां इस्तीफा नहीं होता है। देशने देखा भी कि चाहे विवादमें फंसनेपर तत्कालीन राज्यमंत्री कौशल किशोरका मामला हो, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंहका, अजय मिश्र टेनीका अथवा हरदीप सिंह पुरीका, विपक्षके चौतरफा दबावके बावजूद सरकारकी सेहतपर कोई असर नहीं पड़ा। किसीका इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन सीजेपीके एक धरनेने सरकारकी चूलें हिला दीं।

काकरोच नाम भले ही मजाकिया लगे, परन्तु इसके पीछेका गुस्सा और अनुभव बहुत गहरा है। काकरोचका स्वभाव क्या है। वह अंधेरेमें रहता है, गन्दगीमें पनपता है, रोशनी पड़ते ही भागता है मारो तो और तेजीसे फैलता है। सबसे बड़ी बात उसकी प्रजाति कभी खत्म नहीं होती। यही दावा अभिजीत दीपके भी करते हैं। शिक्षामंत्री पदसे धर्मेन्द्र प्रधानके इस्तीफेके बाद अभिजीत दीपके और उनकी टीमके नेता अपनेको बिना चुनावी राजनीतिमें उलझे सुपर सरकार मानने लगे। विपक्षी पार्टियां भी मनसे, बेमनसे उनके पीछे-पीछे चलने लगीं। कारण यह कि विपक्ष सरकारके खिलाफ सड़कपर उतरकर आन्दोलन करनेकी हालतमें नहीं रह गया है। वहां कार्यकर्ता कम नेता अधिक हो गये हैं। सीजेपीको यह स्पेस अच्छा दिखा। उसके नेता देशभरके स्कूलोंकी दशा सुधारनेके लिए कई राज्योंमें घूमने लगे। राजस्थानमें तो पिटे भी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्रमें विरोध झेला। लेकिन उसके पहले झारखंडमें छात्रोंके आन्दोलनसे दूरी बना ली। पंजाबके स्कूलोंकी बेहतरीकी बात करने लगे। इससे संदेह गहराया। पड़तालमें पता चला कि सीजेपीके पूरे नेतृत्वका पूर्वमें आम आदमी पार्टीसे जुड़ाव रहा है। इससे सरकारको उन्हें घेरनेका बढ़िया मौका मिल गया। उधर, गाहे बगाहे सीजेपीके लोग अदालतोंके खिलाफ भी बेवजहकी टिप्पणी करने लगे। इससे भी लोगोंका मोहभंग हुआ।

यह सही है कि देशके हालात आन्दोलनके लिए मुफीद हैं। जनता बढ़ती महंगीसे कराह रही है। आम लोगोंको घरके खर्चे चलानेमें दिक्कत हो रही है। मकान किराया और निजी स्कूलोंकी फीस लगातार बढ़ रही है। कोरोनाके बाद निजी क्षेत्रमें कामगारोंके वेतन-भत्तोंमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, जबकि कामके घंटे बढ़ा दिये गये हैं। सरकारी विभागोंमें जगह खाली होनेके बावजूद बहाली नहीं हो रही है। मुफ्तके खाद्यान्न बांटे जानेके कारण ग्रामीण क्षेत्रोंकी अर्थव्यवस्था भी पटरीसे उतर गयी लगती है। खेतीके लिए कामगार नहीं मिल पा रहे हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। समयपर परीक्षा और परिणाम नहीं आनेसे छात्र निराश हैं। वाहनों, मकानोंकी किस्त नहीं भर पानेके कारण मध्यम वर्ग वेदनासे भरा हुआ है। हताशामें आत्महत्याकी घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर सरकारकी ढपोरशंखी बड़ी-बड़ी बातें आम आदमीके गुस्सेको और बढ़ा रही हैं। सरकारकी कोशिश देशके चहुंमुखी विकासकी गति तेज करनेकी बनिस्बत जातिका समीकरण ठीक करने, धर्मके ध्रुवीकरण और बूथ मैनेजमेंटपर ज्यादा दिखाई देती है।

एक अंग्रेजी समाचार-पत्रमें चुनाव आयोगमें मतभेदकी खबर छपनेके बाद विपक्ष गोलबंद होने लगा। लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले सवा सालसे चुनाव आयोगके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन उन्हें विपक्षी दलोंका भी भरपूर समर्थन नहीं मिलता था। बिहारमें राष्ट्रीय जनता दलके नेता तेजस्वी यादव भले ही कुछ दिन राहुलके साथ चले लेकिन बादके दिनोंमें चुनावमें टिकट बांटने और प्रचार कार्यमें लगे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि वह अकेले ही सरकार बना लेंगे। यही स्थिति पश्चिम बंगालमें ममता बनर्जीकी थी। महाराष्ट्रमें शरद पवार और संजय राउत सिर्फ एक्सपर बयान देकर अपना कर्तव्य निभा गये। दक्षिण और पूर्वोत्तरमें भी यही हालात थे। अखबारमें खबर छपनेके बाद और चुनावोंमें बुरी तरह हार जानेके बाद विपक्ष गोलबंद हुआ। ऐसेमें सीजेपीके नेताओंको लगा कि बहती गंगामें हाथ धो लें तो विपक्षके सिरमौर हो जायंगे। उधर, पहलेसे खार खायी सरकार काकरोचोंको नेस्तनाबूद करनेके लिए पहलेसे तैयार बैठी थी। १० अक्तूबरको अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांकाको दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन रिहा किया तो शांति बनाये रखनेकी शर्तोंके साथ बेल बांड भरवाकर छोड़ा।

यही कारण है कि १४ अक्तूबरको दोबारा जंतर-मंतरपर गिरफ्तार होनेके बाद सौरभ दास और आशुतोष रांकाको जेलसे जमानत मिलनेमें हफ्तेभरसे ज्यादा समय लग गया। सीजेपीके एक और रणनीतिकार अकिंज्य शिंदे भी शर्तोंके साथ बेलबांड भरकर ही बाहर आये हैं। इससे काकरोच जनता पार्टीके सामने कई मुश्किलें दिख रही हैं। दिल्ली हाईकोर्टके न्यायाधीशने उन्हें जेन जी माननेसे इनकार कर दिया है। शर्तोंके अनुसार आगेकी आन्दोलनके लिए उन्हें पुलिसकी अनुमति लेनी होगी। पुलिस अनुमति देगी तो नये शर्तोंके साथ देगी। शर्तोंको तोड़ा तो फिर जेल जाना होगा। ऐसेमें कानूनी बेड़ियोंके साथ अब उनके लिए आन्दोलनकी राह और कठिन हो गयी है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह कि काकरोच जनता पार्टीकी कोशिशें बुलबुला बनकर रह जायंगी अथवा सड़कोंपर अराजकता फैलाकर देशके लोकतांत्रिक स्वरूपको अस्थिरताकी बाढ़में डूबो देंगी।



ज्ञान और विवेक

❐ श्रीश्री रविशंकर

क्या तुमने ध्यान दिया है कि प्रत्येक क्षण तुम्हारे मनमें क्या चल रहा होता है। मन इसी उधेड़बुनमें रहता है कि आगे क्या होगा। ज्ञानमें मनके इस रूपके प्रति सजगता आती है कि इस पल मनमें क्या घट रहा है। पुस्तकें पढ़कर अन्य सभी प्रकारकी जानकारी तथा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। चाहे जन्म हो मृत्यु या खान-पानकी आदत। किसी भी विषयपर अनगिनत पुस्तकें उपलब्ध हैं। परन्तु अपने मनके प्रति जागरूकता पुस्तक पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। हमारा मन वह अतीत और भविष्यके बीच डोलता है। प्रत्येक क्षण या तो वह अतीतको लेकर क्रोधित है या भविष्यको लेकर व्याकुल। एक और प्रवृत्ति है मनकी नकारात्मक बातोंसे चिपके रहने की। यदि दस सकारात्मक घटनाओं या दृष्टांतोंके बाद एक नकारात्मक बात घटती है तो हम उन दस अच्छी बातोंको एकदम भूलकर उस एक नकारात्मक घटनासे चिपक जाते हैं। मनकी इन दोनों प्रवृत्तियोंके प्रति जागरूकता तुम्हें सहज और सरल बनायगी। यह बेहद अनमोल मूल्य है, जो तुम्हें अंदरसे खिलनेमें सक्षम बनायंगे। दरअसल इस पवित्रताके साथ हमारा जन्म होता है। परन्तु जैसे-जैसे हम अधिकसे अधिक परिपक्व और होशियार बनते जाते हैं इस सरलताको खोते हुए रुखे बनते जाते हैं। जब तुम बच्चे थे तो कोई समस्या नहीं थी। आज लड़ लेते तो अगले ही दिन दोस्ती हो जाती, परन्तु जैसे-जैसे बड़े होते गये, उलझते गये। ज्ञान और विवेकके अभावमें हम एक-दूसरेसे उलझ जाते हैं। हमारे मनमें घृणा, द्वेष और लालसा भरी हुई है। किसीके मनमें झांक कर देखो। कहीं अन्यके प्रति अति अधिक ज्वरभाव है तो कभी भविष्यके लिए लालसा या फिर अतीतके प्रति द्वेष। ज्ञान और विवेक द्वारा हम समाजमें सुव्यवस्थाको बढ़ावा दे सकते हैं। हमें स्वयंका अध्ययन करना है। जीवन जीनेके लिए सारी बातें सीखनेमें हमनें कितना ही समय खर्च किया परन्तु खुद जीवनके बारेमें कितना कम जानते हैं। संसारमें आनेके बाद जो काम हमने सबसे पहले किया वह था एक गहरी सांस लेना और इस संसारमें जो अंतिम काम हम कर रहे होंगे वह है सांस छोड़ना। पहली बार सांस लेने और आखिरी बार सांस छोड़नेके बीच जो कुछ भी है, उसे हम जीवन कहते हैं। हमने कभी भी अपनी सांसपर ध्यान नहीं दिया। शरीर और मनके बीचका संपर्क सूत्र है सांस और इसके द्वारा मनको वर्तमानमें टिका सकते हो। श्वासपर ध्यान बनाये रखनेका दूसरा साधन है सेवा। जब सेवाको जीवनका परम ध्येय बना लेते हो, तब भय दूर होता है और मन केंद्रित हो जाता है।

आखिर कब थमेगा धार्मिक आयोजनोंमें मौतका सिलसिला

❐ योगेश कुमार गोयले

धर्म, आस्था और विश्वासके केन्द्रोंपर इंसान सुकून, शांति और सुख-समृद्धिकी कामना लेकर पहुंचता है लेकिन जब वही स्थान चीख-पुकार, दमघोंटू भीड़ और मौतके मंजरमें तब्दील हो जायं तो यह हमारी व्यवस्थाकी संवेदनहीनता और सुरक्षा संबंधी तैयारियोंकी विफलताका भयावह प्रमाण है। कोलकाताके चोरबागान दुर्गा पूजा पंडालमें १७ अक्तूबरकी शाम भगदड़ जैसी स्थितिमें १९ लोगोंकी मौत और दो दर्जनसे अधिक लोगोंके घायल होनेकी खबरने एक बार फिर देशको झकझोर दिया। सप्तमीकी शाम मां दुर्गाके दर्शनकी लालसा लेकर निकले श्रद्धालुओंको क्या पता था कि घर लौटनेके बजाय कई परिवारोंको अपने प्रियजनोंके शव मिलेंगे। जिस उत्सवमें जीवन, शक्ति और विजयका सन्देश गूंजना चाहिए था, वहां मातम पसरा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारी आस्थाके स्थलोंपर इंसानी जिन्दगी इतनी सस्ती क्यों हो जाती है।

चोरबागानकी घटनाको केवल अचानक उमड़ी भीड़ या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताकर जिम्मेदारीसे बचना आसान है लेकिन ऐसा करना त्रासदीके वास्तविक कारणोंसे आंखें मूंदना होगा। बारिशके बीच पंडालमें प्रवेश और निकासके रास्तोंपर भीड़का दबाव बढ़ा और अफरा-तफरीकी स्थिति पैदा हुई। घटनास्थलकी संकरी गलियों, लोगोंकी आवाजाही तथा सुरक्षा प्रबंधोंको लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि दुर्घटनाके वास्तविक कारणों और जिम्मेदारीका निर्धारण निष्पक्ष जांचसे ही होना चाहिए। फिर भी, यदि भारी भीड़ और खराब मौसमके बावजूद आवाजाहीको सुरक्षित रखनेकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो यह गम्भीर प्रशासनिक और आयोजन संबंधी विफलताका मामला है। जब किसी आयोजनमें हजारों लोगोंके जुटनेकी संभावना पहलेसे मालूम हो, तब संभावित खतरेका अनुमान लगानेके लिए दुर्घटना होनेकी प्रतीक्षा क्यों की जाती है।

भारतमें धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनोंमें भगदड़ कोई नयी समस्या नहीं है। मंदिरों, तीर्थस्थलों, धार्मिक मेलों, जुलूसों और पर्व-समारोहोंमें भीड़का बेकाबू होना बार-बार जानलेवा साबित होता रहा है। वर्ष २००५ में महाराष्ट्रके मांढरदेवी मंदिरमें भगदड़से ३०० से अधिक लोगोंकी मौत हुई थी। २०११ में केरलके सबरीमालामें भगदड़ने सौसे अधिक लोगोंकी जान ले ली थी। २०१३ में मध्य प्रदेशके रतनगढ़ मंदिरमें सौसे अधिक लोगोंकी मौत हुई। २०२२ में जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिरमें भगदड़से १२ श्रद्धालुओंकी जान गयी। २०२४ में हाथरसमें धार्मिक सत्संगके बाद मची भगदड़में १२१ लोगोंकी मौतने पूरे देशको स्तब्ध कर दिया। २०२५ में प्रयागराज महाकुम्भ और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशनपर भी भीड़से जुड़ी जानलेवा घटनाओंने सार्वजनिक सुरक्षाकी तैयारियोंपर गम्भीर प्रश्न खड़े किये थे। हालांकि अलग-अलग घटनाओंके कारण और परिस्थितियां भिन्न थी लेकिन इनके बीच एक चिन्ताजनक समानता रही, भीड़के दबावमें इंसानी जीवनकी असुरक्षा।

हर त्रासदीके बाद शोक संदेश जारी होते हैं, मुआवजेकी घोषणाएं होती हैं, जांच समितियां गठित की जाती हैं और इसके बाद व्यवस्था फिर पुराने ढर्रेपर लौट जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी विफलता है। यदि पिछली दुर्घटनाओंसे सबक लेकर प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित किया गया होता तो बार-बार ऐसी मौतोंका सामना नहीं करना पड़ता। जांचका उद्देश्य केवल दोषियोंकी पहचान करना नहीं, उन खामियोंको दूर करना भी होना चाहिए, जिनके कारण एक ही प्रकारकी त्रासदियां बार-बार सामने आती हैं। सवाल यह नहीं कि अगला हादसा कहां होगा, बल्कि यह है कि उसे रोकनेके लिए हमने अबतक क्या किया है। यह समझना जरूरी है कि भगदड़ केवल लोगोंके अचानक दौड़नेसे नहीं होती। जब किसी सीमित स्थानमें भीड़की संख्या उसकी क्षमतासे अधिक हो जाती है, प्रवेश और निकासका प्रवाह बाधित होता है, लोग एक-दूसरेको धक्का देने लगते हैं या अफवाहके कारण एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब स्थिति तेजीसे जानलेवा बन सकती है। भीड़के अत्यधिक दबावमें व्यक्तिके लिए सांस लेना और स्वयंको संभालना कठिन हो जाता है। गिरने वाला व्यक्ति दूसरोंके लिए भी गम्भीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे हालातमें कुछ क्षणोंकी अव्यवस्था भी अनेक जिन्दगियां लील सकती है। इसलिए भीड़ प्रबंधनका अर्थ केवल पुलिसकर्मियोंकी तैनाती, बैरिकेडिंग या लाउडस्पीकरसे घोषणाएं करना नहीं है। इसके लिए भीड़की क्षमताका वैज्ञानिक आकलन, आवाजाहीकी सतत निगरानी, प्रशिक्षित कर्मियों और स्पष्ट आपातकालीन योजनाकी आवश्यकता होती है।

धार्मिक आयोजनोंमें सुरक्षाको अक्सर आस्थाके उत्साह और आयोजनकी भव्यताके पीछे गौण कर दिया जाता है। ऊंचे-ऊंचे पंडाल, आकर्षक सजावट, रोशनी, प्रचार और प्रायोजकोंकी प्रतिस्पर्धापर भरपूर ध्यान दिया जाता है लेकिन प्रवेश द्वार कितने हैं, निकास कितना चौड़ा है, आपातकालीन रास्ते खु